

प्रेषक/ शिकायतकर्ता  
पीपी कपूर,  
सामाजिक एवं आरटीआई एक्टिविस्ट  
निकट बंसल फाउण्ड्री,  
जीटी रोड समालखा-132101, पानीपत  
मो:- 8708272105

सेवा में

जस्टिस हरिपाल वर्मा,  
माननीय लोकायुक्त हरियाणा,  
नव सिविल सचिवालय, हरियाणा  
सैक्टर-17, चंडीगढ़-160017

**विषय:हरियाणा के सभी 88 शहरों में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के तहत प्रॉपर्टी  
आईडी सर्वे में किए गए घोटाले की सीबीआई जांच कराने हेतु शिकायत।**

**विरुद्ध:-**

1. श्री कमल गुप्ता, मंत्री शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़
2. श्री डीके बेहरा आईएएस, तत्कालीन निदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा, पंचकूला
3. श्री धीरेन्द्र खड़घटा आईएएस  
तत्कालीन कमिशनर, नगर निगम रोहतक।
4. श्री प्रदीप दहिया आईएएस,  
तत्कालीन कमिशनर नगर निगम हिसार
5. श्री यशेन्द्र सिंह आईएएस  
तत्कालीन कमिशनर नगर निगम, पानीपत
6. कु० मोनिका गुप्ता आईएएस  
तत्कालीन कमिशनर नगर निगम, सोनीपत



7. श्री नरेश नरवाल आईएएस  
तत्कालीन कमिशनर नगर निगम करनाल
8. श्री पार्थ गुप्ता आईएएस  
तत्कालीन कमिशनर नगर निगम अंबाला
9. श्री जितेन्द्र दहिया आईएएस  
तत्कालीन कमिशनर नगर निगम फरीदाबाद
10. श्री मुकेश आहुजा आईएएस  
तत्कालीन कमिशनर नगर निगम गुरुग्राम
11. श्री आयुष सिन्हा, आईएएस  
तत्कालीन कमिशनर नगर निगम यमुनानगर
12. श्री धर्मबीर, आईएएस  
तत्कालीन कमिशनर नगर निगम, पंचकूला
13. श्री मनिन्द्र सिंह, तत्कालीन ईओ, नगर परिषद हांसी (हिसार)
14. श्री दीपक गोयल, तत्कालीन ईओ, नगर परिषद गोहाना
15. श्री मनिन्द्र सिंह, तत्कालीन ईओ, नगर परिषद होडल
16. श्री अभय सिंह, तत्कालीन ईओ, नगर परिषद रेवाड़ी
17. श्री संदीप मलिक, तत्कालीन ईओ, नगर परिषद सिरसा
18. श्री मनोज यादव, तत्कालीन ईओ, नगर परिषद पलवल
19. श्री सुनील रंगा, तत्कालीन सचिव, नगरपालिका तावडू (जिला नूंह)
20. श्री राकेश वालिया, तत्कालीन सचिव, नगरपालिका रादौर (यमुनानगर)
21. श्री अशोक कुमार, तत्कालीन सचिव, नगरपालिका लाडवा
22. श्री नरेन्द्र सैनी, तत्कालीन सचिव, नगरपालिका सांपला (रोहतक)
23. श्री प्रशांत पराशर, तत्कालीन सचिव, नगरपालिका महम (रोहतक)
24. श्री तेजपाल, तत्कालीन सचिव, नगरपालिका कलानौर (रोहतक)
25. श्री प्रदीप खर्ब, तत्कालीन सचिव, नगरपालिका समालखा (पानीपत)
26. श्री मुकेश कुमार तत्कालीन सचिव, नगरपालिका कनीना (महेन्द्रगढ़)
27. उक्त अधिकारियों के अतिरिक्त प्रदेश की अन्य सभी नगर परिषदों के तत्कालीन ईओ, नगरपालिकाओं के तत्कालीन सचिवों व शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के

तत्कालीन अन्य अधिकारीगण (जिनके नाम निदेशालय शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास हैं)।

माननीय महोदय,

मैं पीपी कपूर पुत्र श्री बिलास राज कपूर जो कि सक्रिय सामाजिक एवं आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ व समालखा जिला पानीपत निवासी 62 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक हूँ। शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के अंतर्गत पूरे हरियाणा के सभी 11 नगर निगमों, 23 नगर परिषदों व 54 नगरपालिकाओं में प्रॉपर्टी आईडी सर्वे के नाम पर एक बहुत बड़ा घोटाला, जालसाजी, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी सभी 88 नगर निकायों के तत्कालीन आयुक्तों, कार्यकारी अधिकारियों व पालिका सचिवों ने याशी कन्सल्टिंग कम्पनी जयपुर (कांटेक्टर फर्म) के साथ मिलीभगत करके की है, इसमें श्री डीके बेहरा तत्कालीन निदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा व श्री कमल गुप्ता मंत्री शहरी स्थानीय निकाय विभाग भी संलिप्त हैं। इसका खामियाजा प्रदेश के सभी शहरों की सभी कुल 42.50 लाख संपत्तियों के मालिक बुरी तरह से भुगत रहे हैं। भ्रष्टाचारियों की मौज बनी हुई है, जनता में हाहाकार है, कोई सुनने वाला नहीं है।

**प्रदेश व्यापी प्रॉपर्टी आईडी सर्वे घोटाले के बारे मेरी शिकायत इस प्रकार है:-**

1. दिनांक 13/08/2019 को निदेशक शहरी स्थानीय विभाग हरियाणा पंचकूला व मैसर्स याशी कन्सल्टिंग सर्विसेज प्रा.लि. (पता: 501-510, 5वीं मंजिल कैलाश टावर, टोंक रोड, लाल कोठी एरिया, जयपुर-302017 (राजस्थान) मैनेजिंग डायरेक्टर श्री संजय गुप्ता मो०: 9425111561) के बीच हरियाणा के सभी 88 नगर निकायों में स्थित सम्पत्तियों की आईडी बनाने के लिए जीओ सर्वे कार्य को ठेके पर देने का लिखित एग्रीमेंट पंचकूला में हुआ। टेंडर एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक यह प्रॉपर्टी आईडी सर्वे कार्य याशी कंपनी को दिनांक 12 दिसम्बर 2019 तक पूरा करना था। लेकिन इस नकारा कांटेक्टर फर्म याशी कम्पनी पर उक्त सभी अधिकारी व प्रदेश सरकार इतने मेहरबान रहे कि इसे फेज-1 का सर्वे कार्य पूरा करने के लिए दस बार एक्सटेंशन दी गई। लेकिन निर्धारित अवधि के 3 वर्ष बाद भी फेज-1 का सर्वे कार्य अधूरा व बोगस मिला।
2. प्रदेश के सभी शहरों में कुल 42.50 लाख संपत्तियों के कथित तौर पर किए गए प्रॉपर्टी आईडी सर्वे का कांटेक्टर फर्म (मैसर्स याशी कन्सल्टिंग सर्विसेज प्रा.लि.) ने 99 प्रतिशत गलत सर्वे किया। जिस कारण पूरे हरियाणा में हाहाकार मची हुई है। प्रॉपर्टी आईडी ठीक

*Handwritten signature*

करवाने के लिए व नो-ड्यूज सर्टिफिकेट लेने के लिए जनता धक्के खा रही है, दलालों को मोटी घूस देकर काम करवाने को विवश है। सभी नगर निकायों में कार्यरत संबंधित स्टाफ पर इन त्रुटियों को ठीक करने का अतिरिक्त बोझा बेवजह लाद दिया गया है। कंपनी को 60 करोड़ रुपये देकर मौज करने के लिए छोड़ गया है।

3. लेकिन शहर स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के अंतर्गत प्रदेश के सभी नगर निकायों, नगर निगमों, नगर परिषदों व नगरपालिकाओं के उक्त सभी अधिकारियों ने याशी कम्पनी के 99 प्रतिशत गलत प्रॉपर्टी आईडी सर्वे को शतप्रतिशत सही बताते हुए क्लीनचिट देते हुए आवश्यक साईन ऑफ सर्टिफिकेट जारी करके याशी कम्पनी को करीब 60 करोड़ रुपये की पेमेंट का भुगतान करवा कर घोटाला किया।

सबूत के रूप में नगर निगम रोहतक के तत्कालीन कमिशनर श्री धीरेन्द्र खरकड़ा, आईएस द्वारा दिनांक को जारी किए गए साईन ऑफ सर्टिफिकेट की छाया प्रति सबूत की (Annex...1) संलग्न है। इसी तरह दिनांक नगर निगम हिसार के तत्कालीन कमिशनर श्री प्रदीप दहिया आईएस द्वारा जारी साईन ऑफ सर्टिफिकेट की छाया प्रति (Annex...2) संलग्न है। इन सर्टिफिकेट्स में इन अधिकारियों ने लिखित रूप से बताया है कि याशी कम्पनी द्वारा किए गए प्रॉपर्टी आईडी सर्वे की वैरिफिकेशन उपरांत उन्हें इस सर्वे कार्य में कोई त्रुटि नहीं मिली। याशी कम्पनी को क्लीनचिट दी तभी इस कम्पनी को पेमेंट हुई। याशी कम्पनी को क्लीनचिट देकर 60 करोड़ रुपये की पेमेंट कराने का यही फर्जीवाड़ा, जालसाजी, भ्रष्टाचार पूरे हरियाणा के सभी कुल 89 नगर निकायों (नगर निगमों, नगर परिषदों, नगरपालिकाओं) में किया गया।

4. टैंडर एग्रीमेंट की शर्त संख्या 37.6.7 (Annex...3 छाया प्रति संलग्न है) के अनुसार कान्ट्रेक्टर फर्म (याशी कम्पनी) द्वारा किए गए प्रॉपर्टी आईडी सर्वे की वैरिफिकेशन उक्त अधिकारियों को करनी थी। वैरिफिकेशन में प्रॉपर्टी आईडी सर्वे कार्य सही पाए जाने पर ही उक्त अधिकारियों को साईन ऑफ सर्टिफिकेट जारी करने थे, तभी पेमेंट होनी थी। लेकिन उक्त सभी अधिकारियों ने इस सर्वे में 95 प्रतिशत त्रुटियां होने के बावजूद साईन ऑफ सर्टिफिकेट जारी करके करीब 60 करोड़ रुपये की धनराशि की पेमेंट याशी कंपनी को करवाकर घोटाला व भ्रष्टाचार किया है। इतना बड़ा घोटाला व फर्जीवाड़ा सरकार के संरक्षण के बगैर असंभव है।

5. इस भ्रष्टाचार घोटाले को स्वीकार करते हुए प्रदेश के शहरी स्थानीय विभाग के मंत्री श्री कमल गुप्ता ने खुद स्वीकार किया है कि अधिकारियों ने डेटा वैरिफाई करके सर्टिफिकेट कम्पनी को दिया तभी भुगतान हुआ। इस संबंध में दिनांक 18 दिसम्बर 2022 को दैनिक भास्कर, पानीपत के हरियाणा पृष्ठ पर प्रकाशित न्यूज की छाया प्रति सबूत (Annex...4) संलग्न है। स्पष्ट है कि घोटाला, भ्रष्टाचार माननीय शहरी निकाय मंत्री श्री कमल गुप्ता के संज्ञान में होने के बावजूद उन्होंने ना तो उक्त दोषी अधिकारियों व दोषी कम्पनी पर कोई कारवाई ना करके गंभीर अपराध किया है। स्पष्ट है कि वह खुद इस घोटाले में संलिप्त हैं इसलिए वे कम्पनी का बचाव कर रहे हैं व दोषी अधिकारियों पर भी कोई कारवाई नहीं कर रहे हैं।

6. शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के मंत्री श्री कमल गुप्ता ने खुद स्वीकार किया है कि याशी कंपनी द्वारा प्रदेश में कुल 42.70 लाख प्रॉपर्टी आईडी का जो सर्वे किया गया है उसमें से 15.50 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी आईडी में त्रुटियां यानि प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में 36.30 प्रतिशत त्रुटियां पाई गई हैं। इस संबंध में दिनांक 17 दिसम्बर 2022 को दैनिक भास्कर पानीपत ने हरियाणा पृष्ठ पर प्रकाशित न्यूज की क्लिपिंग Annex...5 संलग्न है। टैंडर एग्रीमेंट के पृष्ठ न. 53 पर सर्विस लेवल पैनल्टी क्लॉज के क्रमांक न. 5 छाया प्रति संलग्न है Annex...6। पर लिखित शर्त के मुताबिक 20 प्रतिशत से अधिक त्रुटियां पाए जाने पर सर्वे कार्य ठेका रद्द किया जाना था। लेकिन प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में 36.30 प्रतिशत त्रुटियां सरकारी मुताबिक भी पाए जाने के बावजूद ठेका रद्द नहीं किया गया। पैनल्टी क्लॉज की उक्त शर्त में साफ लिखा है कि :-

**For submitted property survey data of any land/asset property, if there is more than 20% of error identified by the audit agencies === Termination of contract without cleaning any of the pending invoices.**

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ये घोटाला व भ्रष्टाचार शहरी स्थानीय निकाय विभाग मंत्री के संज्ञान में होने के बावजूद आज तक ना तो इस घोटाले की जांच कराई, ना ही दोषियों को दंडित किया। जिससे साफ है कि शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री कमल गुप्ता भी इस घोटाले में संलिप्त हैं।

*Handwritten signature*

7. इस घोटाले के कारण सभी 88 शहरों की कुल 42.50 लाख संपतियों के मालिक बुरी तरह से पिस रहे हैं। इस घोटाले में उक्त अधिकारियों के इलावा हरियाणा सरकार सीधे तौर पर संलिप्त है। वरना ये सभी दोषी अधिकारी क्यों गलत वैरिफिकेशन रिपोर्ट बनाकर साईन ऑफ सर्टिफिकेट जारी करके डिफाल्टर कम्पनी को 60 करोड़ रुपये का भुगतान कराते? इतना ही नहीं प्रदेश सरकार ने घोटाला जगजाहिर होने के बावजूद ना तो गलत साईन ऑफ सर्टिफिकेट जारी करने के दोषी उक्त अधिकारियों पर कोई एफआईआर दर्ज कराई ना ही याशी कम्पनी को ब्लैकलिस्ट करके दोबारा सही प्रॉपर्टी आईडी सर्वे किसी अन्य कम्पनी से कराया। ना ही पेमेंट के भुगतान पर रोक लगाई। क्यों इस याशी कम्पनी को 60 करोड़ रुपये का भुगतान किया और ना ही जुर्माना लगाया, ऐसा क्यों? इन गंभीर सवालियों का जवाब उक्त सभी अधिकारियों सहित श्री कमल गुप्ता मंत्री हरियाणा सरकार को देना होगा।
8. प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में याशी कम्पनी द्वारा 99 प्रतिशत त्रुटियां होने के बावजूद ना तो पेमेंट रोक़ी, ना उस पर कोई जुर्माना लगाया, ना ठेका रद्द करके उसे ब्लैकलिस्ट किया। वर्क ऑर्डर के पृष्ठ न. 52 पर लिखी शर्त संख्या 41.5 सर्विस लेवल एग्रीमेंट (एसएलए) मॉनिटरिंग (Annex...7 छाया प्रति संलग्न है) के अनुसार डीयूएलबी हरियाणा ने इस पूरे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करनी थी जो नहीं करके अपराध किया है। जबकि नियमानुसार टैंडर के पेज 52 व 53 पर लिखित सर्विस लेवल/पैनल्टी नियम (छाया प्रति संलग्न Annex...8) के क्रमांक न. 5 के अनुसार 20 प्रतिशत से ज्यादा त्रुटियां होने पर ठेका रद्द करना था। लेकिन 95 प्रतिशत त्रुटियां होने पर भी कंपनी पर कोई कारवाई नहीं की गई। इसी प्रकार टैंडर एग्रीमेंट की शर्त न. 41. 4 ब्रीच क्लॉज के बिन्दु (एफ व एच) (छाया प्रति संलग्न है Annex...9) के तहत ना तो ठेका रद्द किया ना ही याशी कम्पनी की प्रफॉर्मेंस बैंक गारन्टी जब्त की गई। उक्त टैंडर एग्रीमेंट के पेज न. 51 के बिन्दु न. 41. 4 Breach Clause का बिन्दु न. 41.4 (एफ) जोकि इस प्रकार है:- Before centralized system operation and maintenance face and during centralized system implementation/development phace, the maximum penalty shall be capped 10% of the total project value. If the penalty during this phases exceeds 10% of the total project value The Directorate of

**Urban Local Bodies (DULB) reserve the right to terminate the contract.**

**Clause 41.4 (h):- If penalty calculation exceed 10% of the quarterly payment for two consecutive quarter, The Directorate of Urban Local Bodies (DULB) can take appropriate action including termination of the contract and the forfeiting of Performance Bank Guarantee.**

स्पष्ट है कि ये सब घपला निदेशालय डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडिज हरियाणा कार्यालय के संबंधित उच्च अधिकारियों व प्रदेश की सरकार के संरक्षण में किया गया। पब्लिक को घूसखोरों से लुटने-पिटने, धक्के खाने के लिए छोड़ दिया। ना ही गलत वैरिफिकेशन रिपोर्ट बनाकर साईन ऑफ सर्टिफिकेट जारी करके याशी कम्पनी को 60 करोड़ रूपये की पेमेंट कराने वाले उक्त दोषी सभी अधिकारियों पर कोई एफआईआर दर्ज कराई, ना ही कोई कारवाई की। इस बारे सबूत के तौर पर दैनिक भास्कर दिनांक 30 अप्रैल 2023 की न्यूज क्लिपिंग (Annex...10 संलग्न है)। जिसके अनुसार पानीपत नगर निगम की कुल 1,45,795 सर्वे की गई प्रॉपर्टी आईडी में 62,000 त्रुटियां थी लेकिन एक वर्ष में मात्र 20,000 त्रुटियां ही ठीक हो पाई। यानि कि 42.5 प्रतिशत सर्वे कार्य गलत था। यही दुर्दशा पूरे प्रदेश के सभी नगर निकायों में हुई।

9. **वर्क ऑर्डर की शर्त संख्या 40.2.1 ( Annex...11 छाया प्रति संलग्न है ) के तहत गठित प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी ( पीएमसी ) व शर्त संख्या 40.2.2 ( छाया प्रति संलग्न है Annex...12 ) के तहत गठित स्टीयरिंग कमेटी जिसके चेयरमैन श्री डीके बेहरा तत्कालीन निदेशक शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा व इन कमेटियों में शामिल अन्य सभी अधिकारियों ने अपनी-अपनी ड्यूटी का निर्वाह सभी ढंग से नहीं किया। जिस कारण से ये फर्जीवाड़ा, घपला संभव हुआ और पब्लिक को इतनी भारी परेशानी आज तक उठानी पड़ रही है।**
10. **टेंडर एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक इस प्रॉपर्टी आईडी सर्वे कार्य का ऑडिट करवाया जाना था, जोकि अधिकारियों की मिलीभगत से आज तक नहीं हुआ। ये इसलिए नहीं करवाया गया ताकि घोटाले का भंडा फोड़ ना हो सके।**  
**उक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि इस प्रॉपर्टी आईडी सर्वे घोटाले में प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री श्री कमल गुप्ता, तत्कालीन निदेशक, शहरी**


स्थानीय निकाय विभाग श्री डीके बेहरा, उपरोक्त सभी आईएस अधिकारी व अन्य अधिकारी पूरी तरह से सलित हैं, इसलिए हरियाणा सरकार ने ना तो दोषियों के खिलाफ कोई कारवाई की है और ना ही कर पाएगी। इस घोटाले की जांच सही ढंग से सीबीआई से करवाई जानी आवश्यक है ताकि दोषियों को दंडित करवाया जा सके।

अतः इस शिकायत द्वारा माननीय लोकायुक्त महोदय से कृपया प्रार्थना है कि :-

1. हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में किए गए इस घोटाले की सीबीआई जांच करवाकर उक्त सभी दोषी अधिकारियों व शहरी निकाय मंत्री हरियाणा के विरुद्ध क्रिमिनल केस भ्रष्टाचार, घूसखोरी, जालसाजी के अपराध में दर्ज कराकर दंडित किया जाए।
2. प्रॉपर्टी आईडी सर्वे 99 प्रतिशत गलत होने के बावजूद याशी कंस्ट्रिंग सर्विसेज प्रा.लि. जयपुर को भ्रष्टाचार पूर्वक 60 करोड़ रुपये की अदा की गई धनराशि की ब्याज सहित वसूली कराई जाए व भारी जुर्माना लगाकर इस कम्पनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए।
3. इस घोटाले के कारण जनता को हो रही भारी समस्या को हल कराने हेतु व भ्रष्टाचार पर रोक लगवाने के लिए सभी प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे कार्य सही ढंग से करवाकर जनता को राहत दिलाई जाए।

दस्तावेज संलग्न हैं:- 1. कोर्ट फीस राशि 1000/- रुपये का स्टाम्प पेपर, 2. फार्म-1, 3. फार्म-2 शपथपत्र, 4. टैंडर एग्रीमेंट की कॉपी (62 पृष्ठ)

दिनांक: 17/07/2023

  
हस्ताक्षर शिकायतकर्ता  
पीपी कपूर,  
सामाजिक एवं आरटीआई एक्टिविस्ट  
निकट बंसल फाउण्ड्री,  
जीटी रोड समालखा-132101, पानीपत  
मो:- 8708272105



भारतीय कोर्ट फी

भारत

INDIA

एक  
हजार  
रुपये

ONE  
THOUSAND  
RUPEES

1000 रु.

मन्यमेव जयते

Rs. 1000

INDIA COURT FEE

हरियाणा HARYANA

BEFORE Honble Lokayukta Haryana

103777

In Complaint Case dtd. 17/07/2023

P.P. KAPOOR vs. Sh. Karmal Gupta Minister URB Hrg and others

P.P. Kapoor  
(P.P. KAPOOR)  
Complainant

**FORM-1**  
**FORM OF COMPLAINT**  
**BEFORE THE LOKAYUKTA, HARYANA**

Complainant P.P. Kapoor Son of Shri Bilas Raj Kapoor, R.T.I. Activist R/o Near Bansal Foundary, G.T. Road Samalkha , Distt. Panipat, Pin Code 132101

In the matter of allegation against

- (i) Sh. Kamal Gupta, Minister Urban Local Bodies, Haryana , Chandigarh.
- (ii) Sh. D.K. Behra Then Director Urban Local Bodies, Haryana , Panchkulan.
- (iii) Sh. Dhirender Khatkhara Then Commissioner Municipal Corporation, Rohtak.
- (iv) Sh. Pardeep Dahiya IAS Then Commissioner , Municipal Corporation, Hisar.
- (v) And all the Then Commissioner of Municipal Corporation, All the E.O., Municipal Council & All the Secretary Municipal Committees in Haryana State & others.

The above named complainant is satisfied that the aforesaid public servant –

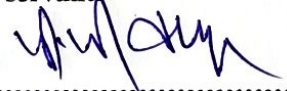
- i) Has knowingly and intentionally abused his position as such as to obtain any undue gain or favour to himself or to any other person or to undue harm to any other person, and/or
  - ii) Was actually in the discharge of his function as such as public servant by corrupt motives, and/or
  - iii) Is guilty of corruption, and/or
- (Strike out the clause or clause not relevant to the complaint)

To support the allegations the complainant relies on the following facts and is also filing an affidavit-

- (i) Copy of Complaint Dated 17-07-2023.
- (ii) Copy of tender Agreement dated 13th August 2019.
- (iii) Copy of News Clipping of Dainik Bhaskar Dated 18-12-2022.
- (iv) Copy of News Clipping of Dainik Bhaskar Dated 17-12-2022.
- (v) Copy of News Clipping of Dainik Bhaskar Dated 30-04-2023.
- (vi) Copy of Sign OFF Certificates of Municipal Corporation Rohtak.
- (vii) Copy of Sign OFF Certificates of Municipal Corporation Hisar.

The complainant has/has not for the same matter resorted to a remedy by way of processing before a tribunal/ a court of law/ an authority empowered to decide the matter particulars of which are as under:- NIL

It is therefore , prayed that an inquiry be made against the public servant

  
.....


Signature/thumb mark of the applicant

**Verification:-**

I P.P. Kapoor son of Shri Bilas Raj Kapoor resident of Samalkha hereby verify that the facts stated by me in paras 1 to 10 in the complaint are true to my personal knowledge and/or the facts stated by me in paras 1 to 10 are based on information received from Documents as above (give the name) and/or documents, and the same are believed by me to be true.

Dated:- 17-07-2023

Place:- Samalkha

  
.....

Signature/thumb mark of the applicant

RAJ  
ST



**Form II**  
**AFFIDAVIT**  
**(Before Lokayukta Haryana)**

I, P.P. Kapoor son of Shri Bilas Raj Kapoor , R.T.I. Activist , Resident of Samalkha, Tehsil Samalkha District Panipat.

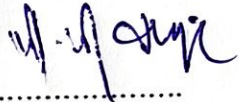
o hereby solemnly affirm and state as follows:-

1) That I am complainant in the case of Property ID Survey Scam.

- (i) Sh. Kamal Gupta, Minister Urban Local Bodies, Haryana , Chandigarh.
- (ii) Sh. D.K. Behra Then Director Urban Local Bodies, Haryana , Panchkulan.
- (iii) Sh. Dhirender Khatkhara Then Commissioner Municipal Corporation, Rohtak.
- (iv) Sh. Pardeep Dahiya IAS Then Commissioner , Municipal Corporation, Hisar.
- (v) And all the Then Commissioner of Municipal Corporation, All the E.O., Municipal Council & All the Secretary Municipal Committees in Haryana State & others.

2. That the statements of this complaint have been ready by/read over to me and understood/ heard by me and these are true to the best of my knowledge and belief.

3. That the facts stated by me in paras 1 to 10 are true to the best of my knowledge and belief stated in paras 1 to 10 are based on the information and documents which, I believe to be true.

  
.....  
Signature/thumb Mark of the Applicant

Place:- Samalkha  
Dated:- 17-07-2023

Affidavit sworn before me.

Verified that above statement was declared before me on oath/ affirmation this 17<sup>th</sup> day of July 2023 at Samalkha in the district of Panipat by Shri P.P. Kapoor S/o Sh. Bilas Raj Kapoor who was identified by me who is personally known to me. The contents of the above affidavit have been read over and explained to the deponent who admitted the same to be correct and true.

Place:- Samalkha  
Dated:- 17-07-2023

  
.....  
ATTESTED  
Signature/thumb Mark of the Applicant



Notary Panipat  
17-7-2023

## Sign-Off Format for Property Survey (Stage 1.1(C))

## PART-II: Sign-Off by the DMC / CMC / EO / Secretary of the ULB

Sr. No.	Particulars	Totals	
		Online	Offline
1.	Name of ULB	Rohatak	
2.	Nos. of Properties as per RFP	1,73,290	
3.	Nos. of Properties as per Old Demand Registers	1,79,700	
4.	Nos. of Properties available on NDC Portal	1,91,444	
5.	Nos. of Total Properties Surveyed and Submitted by SI on Web Based GIS Platform (Image / Base Map solution for verification covering 100% properties in MC Area) as per prescribed Parameters. (In Excel)	2,04,886	
6.	<b>Data verification by ULB in Stage 1.1(A)</b>		
6(A)	Date & Letter Memo. No.	Letter No. MCR/ZTO/2021/1470-71 dated 19-02-21	
6(B)	No. of Properties certified and verified as per Sign-Off 1.1(A)	1,97,742	
7.	<b>Data validation by ULB in Stage 1.1(B)</b>		
7(A)	Date & Letter Memo. No.	Letter No. MCR/ZTO/2021/1472 dated 19-02-21	
7(B)	No. of Properties certified, verified and validated as per Sign-Off 1.1(B)	1,97,742	
7(C)	No. of Properties selected out of properties submitted by SI (Survey Agency) for physical field verification by the Officer/Officials/Committee (nominated by the concerned MC). (Physical validation of atleast 10% of surveyed properties).	19,000	
7(D)	No. of surveyed properties as mentioned at Sr. No. 7(C), whose data is found correct which is verified and validated.	18,240	
7(E)	No. of surveyed properties as mentioned at Sr. No. 7(C), whose data is found incorrect which is verified and validated.	760	
7(F)	%age of error found in the properties verified.	4.00%	
8.	Nos. of Properties Integrated with OLD P Tax ID on NDC Portal	1,34,313	
9.	%age of Properties Integrated with OLD P Tax ID on NDC Portal	70.16%	
10.	Nos. of Non-Integrated Properties with OLD P Tax ID on NDC Portal	57,131	
11.	%age of Properties not integrated with OLD P Tax IDs on NDC Portal	29.84%	
12.	Nos. of Tax Assessment Information Notices Distributed	2,04,886	
13.	Total Claim/ Objections Received from Citizen both Online and Offline.	Online	Offline
		1,261	13,379
		Total: 14,640	
14.	Total Claim/ Objections Resolved	14,640	

15.	<b>Total Claim/ Objections Rejected</b>	903
16.	Masters' data created for Wards, Sector, Colony, Street, Society and Zone, etc. in PDF Format. <ul style="list-style-type: none"> <li>All Certified Boundaries (MC, Wards, Sectors, etc.)</li> <li>Colony &amp; Layout Plans of planned colonies</li> <li>Street Codes with levels</li> <li>Society Codes if applicable</li> <li>Area Type Codes</li> </ul>	Received all data
17.	Date of Submission of Stage 1.1 (C) data by Survey Agency (SI) to MC in Excel format to verify Claim & Objection properties disposed off which were received during reassessment process. (As per Stage 1.1 (C))	01.09.2022
18.	<b>Whether the Submitted data is Verified.</b>	<b>Yes</b>
19.	No. of Properties taken for verification (10% to be taken up from the list of properties on which claims/objections received from the citizen) Note: Verification is required to be done for all the parameters along with integration for all the properties chosen for verification.	1511
20.	No. of properties where surveyed data based on parameters found incorrect as per SLA.	0
21.	<b>%age of properties found incorrect.</b> Note: %age to be calculated with the number of properties taken for verification as the base.	<b>0%</b>
22.	Properties Updated and Corrected	-

It is to certify that I/We have verified the data of properties submitted by the survey agency for all the prescribed parameters along with integration details.

The Stage 1.1 (C) certification is submitted for releasing the payment under Stage 1.1 (C) to the Survey Agency subject to the decisions of Steering Committee taken in various meetings.

  
Commissioner  
Municipal Corporation Rohtak

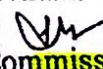
  
- Commissioner,  
Municipal Corporation,  
**ROHTAK**

Memo no.

**1.1 (C) Sign Off certificate is forwarded in original to:**

1. Director, Urban Local Bodies, Haryana, Panchkula for further necessary action.
2. M/s Yashi Consulting Services Pvt. Ltd,

  
Commissioner  
Municipal Corporation Rohtak

  
- Commissioner,  
Municipal Corporation,  
**ROHTAK**



Annex 2/1  
Hissar

**Sign-Off Format for Property Survey (Stage 1.1(C))**  
**PART-II: Sign-Off by the DMC / CMC / EO / Secretary of the ULB**

Sr. No.	Particulars	Details	
1.	Name of ULB	Hissar	
2.	Nos. of Properties as per RFP	1,35,433	
3.	Nos. of Properties as per Old Demand Registers	1,36,063	
4.	Nos. of Properties available on NDC Portal	1,41,939	
5.	Nos. of Total Properties Surveyed and Submitted by SI on Web Based GIS Platform (Image / Base Map solution for verification covering 100% properties in MC Area) as per prescribed Parameters. (In Excel)	1,43,422	
6.	<b>Data verification by ULB in Stage 1.1(A)</b>		
6(A)	Date & Letter Memo. No.	Letter No. MCH/2021/1262-63/PA dated 10-03-21	
6(B)	No. of Properties certified and verified as per Sign-Off 1.1(A)	1,42,322	
7.	<b>Data validation by ULB in Stage 1.1(B)</b>		
7(A)	Date & Letter Memo. No.	Letter MCH/2021/1264-65/PA dated 10-03-21	
7(B)	No. of Properties certified, verified and validated as per Sign-Off 1.1(B)	142322	
7(C)	No. of Properties selected out of properties submitted by SI (Survey Agency) for physical field verification by the Officer/Officials/Committee (nominated by the concerned MC). (Physical validation of atleast 10% of surveyed properties).	15,000	
7(D)	No. of surveyed properties as mentioned at Sr. No. 7(C), whose data is found correct which is verified and validated.	14,340	
7(E)	No. of surveyed properties as mentioned at Sr. No. 7(C), whose data is found incorrect which is verified and validated.	660	
7(F)	%age of error found in the properties verified.	4.40%	
8.	Nos. of Properties Integrated with OLD P Tax ID on NDC Portal	1,00,190	
9.	%age of Properties Integrated with OLD P Tax ID on NDC Portal	70.59%	
10.	Nos. of Non-Integrated Properties with OLD P Tax ID on NDC Portal	41,749	
11.	%age of Properties not integrated with OLD P Tax IDs on NDC Portal	29.41%	
12.	Nos. of Tax Assessment Information Notices Distributed & Submitted Vacant Properties 44540 nos	1,43,422	
13.	Total Claim/ Objections Received from Citizen both Online and Offline.	Online	Offline
		1,550	13,798
		Total: 15,348	
14.	Total Claim/ Objections Resolved	15,348	

*[Handwritten Signature]*

Annex- 2/2

15.	<b>Total Claims/ Objections Rejected</b>	883
16.	Masters' data created for Wards, Sector, Colony, Street, Society and Zone, etc. in PDF Format. <ul style="list-style-type: none"> <li>All Certified Boundaries (MC, Wards, Sectors, etc.)</li> <li>Colony &amp; Layout Plans of planned colonies</li> <li>Street Codes with levels</li> <li>Society Codes if applicable</li> <li>Area Type Codes</li> </ul>	Received all data
17.	Date of Submission of Stage 1.1 (C) data by Survey Agency (SI) to MC in Excel format to verify Claim & Objection properties disposed off which were received during reassessment process. (As per Stage 1.1 (C))	06.09.2022
18.	Whether the Submitted data is Verified.	Yes
19.	No. of Properties taken for verification (10% to be taken up from the list of properties on which claims/objections received from the citizen) <i>Note: Verification is required to be done for all the parameters along with integration for all the properties chosen for verification.</i>	1550
20.	No. of properties where surveyed data based on parameters found incorrect as per SLA.	5
21.	%age of properties found incorrect. <i>Note: %age to be calculated with the number of properties taken for verification as the base.</i>	0.32%
22.	Properties Updated and Corrected	Yes

It is to certify that I/We have verified the data of properties submitted by the survey agency for all the prescribed parameters along with integration details.

The Stage 1.1 (C) certification is submitted for releasing the payment under Stage 1.1 (C) to the Survey Agency subject to the decisions of Steering Committee taken in various meetings.

*[Signature]*  
 Commissioner  
 Municipal Corporation Hisar  
 Commissioner  
 Municipal Corporation  
 HISAR

Dated: 9/9/22

Memo no. 3742 to 42/25A

1.1 (C) Sign Off certificate is forwarded in original to:

1. Director, Urban Local Bodies, Haryana, Panchkula for further necessary action.
2. M/s Yashi Consulting Services Pvt. Ltd.

*[Signature]*  
 Commissioner  
 Municipal Corporation Hisar  
 Commissioner  
 Municipal Corporation  
 HISAR

*[Signature]*

Integrator.

37.6.5. System Integrator shall then complete the milestone based on this list of compliance given by the project Monitoring committee only, without re-visiting checklist parameters that complied earlier and then System Integrator shall intimate The Project Monitoring Committee the compliances of the same in writing, then the process of completion of milestone within seven (07) days by the project Monitoring committee shall become applicable as mentioned above.

37.6.6. The Project Monitoring committee shall then either issue the requisite sign-off (Attached as Schedule VII at Annexure- III of this document) / completion certificate or inform System Integrator the list of compliance to be achieved within (07) days from the date of System Integrator's intimation.

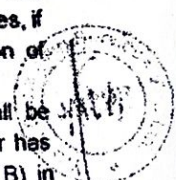
37.6.7. Based on this sign-off certificate, Directorate of Urban Local Bodies (DULB) shall release the payment to System Integrator within forty-five (45) days from the date of sign-off certificate in a centralized manner

✓  
V.I.P.

37.7. Financial Matter

37.7.1. Terms of Payment and Service Credits and Debits

- (i.) In consideration of the Services and subject to the provisions of this Agreement and of the Service Level Agreement (SLA), Directorate of Urban Local Bodies (DULB) shall pay the Service Provider for the Services rendered in pursuance of this Agreement, in accordance with the Terms of Payment Schedule set out in Volume-I of the Request for Proposal (RFP) and subsequent Corrigendum subject always to the fulfilment by the System Integrator of the obligations herein.
- (ii.) All payments are subject to deductions of applicable liquidated damages as provided for in the Service Level Agreement (SLA) section of the Request for Proposal (RFP). For the avoidance of doubt, it is expressly clarified that Directorate of Urban Local Bodies (DULB) shall calculate a financial sum as a result of the failure of the Service Provider to meet the Timelines and/or Service Level Requirements if any, and debit the same against the terms of payment as set out in Payment Schedule in Volume-I of the Request for Proposal (RFP) and subsequent Corrigendum.
- (iii.) Save and except as otherwise provided for herein or as agreed between the Parties in writing, Directorate of Urban Local Bodies (DULB) shall not be required to make any payments in respect of the Services (or without limitation to the foregoing, in respect of the Service Provider performance of any obligations under this Agreement or the Service Level Agreement (SLA) other than those covered in Payment Schedule in Volume-I of the Request for Proposal (RFP) and subsequent Corrigendum.
- (iv.) All payments agreed to be made by Directorate of Urban Local Bodies (DULB) to the Service Provider in accordance with the Project shall be inclusive of all statutory levies, duties, taxes and other charges whenever levied/applicable including costs of maintenance, if any and Directorate of Urban Local Bodies (DULB) shall not be liable to pay any such levies/other charges under or in relation to this Agreement and/or the Services.
- (v.) Payment shall be paid at the times and in the manner set out in the Payment schedule as specified under to Clause 6 of the Volume-I of the Request for Proposal (RFP) and respective corrigendum, against value of contract. However, Service Tax shall be reimbursed against submission of payment proofs. Works contract taxes, if any applicable, shall be reimbursed against actual and against submission of payment proofs.
- (vi.) No invoice for extra work/change order on account of change order shall be submitted by the Service Provider unless the said extra work /change order has been authorized/approved by the Directorate of Urban Local Bodies (DULB) in writing in accordance with Clause on Change order.
- (vii.) In the event of Client noticing at any time that any amount has been disbursed wrongly to the System Integrator or any other amount is due from the System Integrator to the Client, the Client may without prejudice to its rights recover such amounts by other means after notifying the System Integrator or deduct such amount from any payment falling due to the System Integrator. The details of such recovery, if any, shall be intimated to the System Integrator. The System Integrator



*[Handwritten signature]*



# हरियाणा

दैनिक भास्कर, पानीपत, रविवार 18 दिसंबर, 2022

दैनिक भास्कर, पानीपत  
18 दिसंबर 2022

## भास्कर इंटरव्यू • प्रॉपर्टी सर्वे में याशी कंपनी की गड़बड़ी से 15.50 लाख शहरवासी परेशान सवाल: सर्वे में गलती याशी की या अधिकारियों की? मंत्री का जवाब: गलती याशी कंपनी की नहीं, अफसरों ने डेटा वेरिफाई कर सर्टिफिकेट दिया

राजेश सैनी | हिसार

निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने यूएलबी के अफसरों की बताई गलती, लेकिन कार्रवाई किमी पर नहीं

प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे में हुई गड़बड़ी ने आमजन के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों की भी नींद उड़ा रखी है। इसके बावजूद शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि कुछ खामियां जरूर हैं, मगर इसके अलावा सभी गलतियां हैं, जो कंपनी के नाम नहीं धोपी जा सकती। उन्होंने कहा कि टेक्निकली कंपनी पर कार्रवाई नहीं बनती, क्योंकि कंपनी ने सर्वे कर रिकॉर्ड दे दिया। इसके बाद यूएलबी के अधिकारियों के पास डेटा वेरिफाई करने के लिए भेजा गया। इस रिकॉर्ड को प्रवेश के 89 यूएलबी के अधिकारियों ने 10% डेटा रैडमली चेक किया। उन्होंने डेटा को वेरिफाई कर सर्टिफिकेट दिया। फिर डेटा कैसे क्लियर हो गया। याशी कंपनी के सर्वे के रिकॉर्ड को कब तक ठीक कर जनता को गलत मिल पाएगी। इसे ठीक कैसे किया जाएगा। भास्कर के सीधे सवाल पर नगर निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता के जवाब...

प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड ठीक होने में कितना समय लगेगा, क्या जनता को हाल फिलहाल में राहत मिल पाएगी।

1/1 प्रदेश की 42.70 लाख प्रॉपर्टी का सर्वे हुआ। कुछ गलतियां भी हुईं। मगर इसे एकदम से ठीक नहीं किया जा सकता। यह काम कुछ समय के लिए चलता रहेगा। 1 से 2 साल लग सकते हैं डिजिटाइजेशन में शुरुआत में दिक्कत आती है। जब डिपो को किया था, तब भी हंगामा मचा था, लेकिन अब सभी ठसका लाभ उठा रहे हैं।

2/1 क्या याशी कंपनी ने 100 प्रतिशत काम ठीक किया है?

1/1 हमारे अधिकारियों ने सर्वे का डेटा वेरिफाई किया, सर्टिफाई किया, कंपनी ने ऑटो करेक्शन किया तो कंपनी की गलती कैसे हुई। हमारे सभी अधिकारियों ने ही उसे सर्टिफिकेट दिया था।

3/1 अगर अधिकारियों ने वेरिफाई कर दिया तो आज फिर यूएलबी में लोगों की लाइन क्यों लगी है?

1/1 रिकॉर्ड में डेवलपमेंट चार्ज जोड़



4/1 क्या पार्षदों का लिखा मान्य नहीं। दोबारा सर्वे की मांग की है?

1/1 ऐसा नहीं होता कि हाउस के कहने से सब चीजें मान ली जाएं। कार्रवाई बनती है या नहीं, इसको ऊपर भी देखना पड़ता है। उदाहरण के लिए हाउस तो ये पास कर देगा कि ये 25 कॉलोनियां पास हो गईं। क्या हम वो पास कर देंगे। पास करने से पहले नियम के हिसाब से उसे चेक किया जाता है।

दिया गया। अप्रूव्ड कॉलोनी को अनप्रूव्ड कर दिया। इस तरह के मामले अधिक आ रहे हैं। मगर, यह गलती कंपनी की नहीं, इसे समझना होगा।

5/1 गलती याशी की है या अधिकारियों की? जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होगी?

1/1 ये गलती याशी कंपनी की नहीं, अधिकारियों की है। एनडीसी पोर्टल पर मैपिंग गलत की गई। इसके सुधार को लेकर मैंने अभी हाल ही में सभी यूएलबी के हायर अथॉरिटी को मैसेज दे दिया है। दो से तीन दिन के भीतर जो अप्रूव्ड परिया को अनप्रूव्ड में दिखाया

गया है और स्कीम वाली कॉलोनियों या सेक्टरों में जहां डेवलपमेंट चार्ज लगा है। अगर जल्द नहीं हटाया तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

6/1 आपकी पार्टी के पार्षद हिसार के निगम हाउस में प्रस्ताव पास करके नेज चुके हैं। उन्होंने रि-सर्व की मांग की है, सर्वे गलत नहीं तो फिर ऐसा क्यों किया?

1/1 उनके कहने से थोड़े हो पाएंगे। कोई ऐसा एक्शन लेंगे तो यह सारा काम अगले पांच साल भी नहीं हो पाएगा। कई चीजें ऐसी होती हैं, जिसमें कुछ खामियां आई भी होंगी। ऐसी बात नहीं है

कि जब काम में देरी हुई है तो कंपनी की पेंमेंट रोकी भी गई है, लेकिन एक हाउस ने कह दिया तो ऐसे किसी के कहने पर इस्टिमेट स्टेप नहीं ले सकते हैं। अभी तक 30 हजार ऑब्जेक्शन पेंडिंग हैं। हम उन्हें जल्द दूर करवाएंगे।

7/1 क्या यह कंपनी किसी नेता की है या किसी नेता के जानकार की, क्योंकि जनता सीधे आरोप लगा रही है फिर भी कार्रवाई नहीं की जा रही?

1/1 ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई लिखित में शिकायत करें तो हम विजिलेंस जांच करवाने के लिए तैयार हैं। कार्रवाई के लिए कोई आधार तो होना चाहिए।

8/1 कंपनी करोड़ों रुपए लेकर गली जाएगी। आज भी यूएलबी की मैनपावर इसी काम में लगी है। हिसार में इंजीनियर्स भी इस काम में लगाए हैं, आखिर वे गलतियां नज़र क्यों नहीं आ रही?

1/1 कंपनी को जिन शर्तों पर टेंडर दिया गया है, वो रुपए तो दिए जाएंगे। इंटीग्रेशन व नॉन इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट

व अनडेवलपमेंट का काम कंपनी का नहीं था, लेकिन यही तो दुर्भाग्य है कि इन सारे काम को लेकर भी हम कंपनी को ब्लेम कर रहे हैं। इन गलतियों को प्रोजेक्ट इस तरह किया जा रहा है, जैसे कंपनी का काम है।

9/1 इंटीग्रेशन व नॉन इंटीग्रेशन का काम कब तक हो जाएगा, क्या डेडलाइन रखी है। क्या कटम उठाए जाएंगे?

1/1 इंटीग्रेशन और नॉन इंटीग्रेशन का काम 15 जनवरी तक खत्म करने के निर्देश दिए हैं। पूरे प्रदेश में यूएलबी के अधिकारियों के साथ 13 से 14 बार फिजिकल मीटिंग कर चुका हूँ। पहले कुछ खामियां ठीक करने के लिए डीएमसी को पावर दी गई थी। अब इस प्रोसेस को आसान बनाया गया है। फोन नंबर, साइज को लेकर साधारण तरीके से गलतियां ठीक कर सकते हैं। इसके लिए केवल शपथपत्र के माध्यम से करेक्शन हो जाएगा। इसके लिए शिविर भी लगाए जाएंगे। यह कार्य जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं।

# दैनिक भास्कर

आप पढ़ रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय और

इन पहलों बार मेंकेड को टी।

हरियाणा

पानीपत, शनिवार 17 दिसंबर, 2022

पौष कृष्ण पक्ष-नवमी, 2079

## भास्कर Exclusive • याशी के सर्वे में बड़ी लापरवाही, किसी की प्रॉपर्टी किसी के नाम चढ़ाई 42.70 लाख प्रॉपर्टी आईडी में से 15.50 लाख से ज्यादा में गड़बड़ी; मंत्री बोले- ये छोटी गलती

गड़बड़: प्लॉट के साइज गलत भरे, कहीं किराएदार दिखाए मालिक | नियम: सर्वे 20% गलत मिला तो हकीकत: 20-90 प्रॉपर्टी आईडी में गलतियां, कार्रवाई कुछ नहीं

भास्कर न्यूज | हरियाणा विभिन्न जिलों से

### अब लोग आईडी ठीक करने को तैयार हो रहे हैं, प्लॉट के चतुर्भुज काटने को मजबूर

प्रदेश के शहरों में प्रॉपर्टी को लेकर कराए गए सर्वे में लाखों लोगों को परेशानी में डाल दिया है। सर्वे करने वाली याशी कंपनी ने 42.70 लाख प्रॉपर्टी में से 15.50 लाख से ज्यादा में गलत डिटेल्स भर दी हैं। कहीं प्रॉपर्टी दूसरे के नाम चढ़ा दी। फोन नंबर दूसरे लोगों के भर दिए। प्लॉटों के साइज घटा-बढ़ा दिए। कहीं प्लॉट को दो आईडी बना दी तो कहीं दो मकानों को एक प्रॉपर्टी दर्शा दिया। कहीं किराएदारों को ही मालिक दिखा दिया। अब लोग बकाया प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज में दो बड़े कट का फायदा लेने नगर निकाय के कार्यालयों में पहुंचे तो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। इससे लोग कूट का लाभ भी नहीं ले पा रहे। सर्वे कंपनी की गलती के कारण लोगों को गलत बिल भेजा जा रहा है। अब लोग नृटियों को ठीक करने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। लोगों के विभिन्न काम अटक गए हैं। शहर के जनप्रतिनिधि भी सर्वे को गलत ठहरा रहे हैं। हिमाचल, रेवाड़ी समेत कई निकायों ने तो सर्वे को रद्द कर इसे नए सिरे से कराने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। शहरों में 20 से 90% प्रॉपर्टी में गड़बड़ी के बावजूद कंपनी पर कोई कार्रवाई तक नहीं की जा रही। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि छोटी-छोटी गलतियां हुई हैं।

### ये गड़बड़ियां हुईं

- प्रॉपर्टी खरीद गलत भर दिया गया है। वीध कॉलोनी को भी अवैध में डाल दिया।
- कई प्रॉपर्टी दूसरे के नाम चढ़ा दी गई है। किराएदारों को ही मालिक दिखा दिया गया।
- मकान के साइज में गलती की गई है। दो मकानों को एक आईडी बना दी गई।
- फोन नंबर दूसरे जिले के लोगों का दे दिया। 3-4 लोगों के प्लॉट एक के नाम दर्शा दिए।
- एक प्लॉट को दो प्रॉपर्टी आईडी बना दी गई। मकान के कमरों की अलग-अलग आईडी बना दी गई।
- रिहायशी को कॉमर्शियल व कॉमर्शियल को रिहायशी दिखाया। खाली प्लॉट में मकान दर्शा दिए।
- सरकारी जमीन पर बनी जूगियों, ग्रीन बेल्ट तक को आईडी बना दी गई है।

### सर्वे के लिए याशी कंपनी से तय शर्तें

- अगर सर्वे में 5% भी ऑब्जेक्शन आते हैं तो सर्वे दोबारा करना होगा।
- 10% तक गलत है तो दोबारा सर्वे करना होगा। सर्वे के लिए तय हुए प्रति यूनिट रेट का दोगुना जुर्माना भी लगेगा।

### सबसे ज्यादा गड़बड़ी वाले ये 6 जिले

जिला	प्रॉपर्टी आईडी	गलत	जिला	प्रॉपर्टी आईडी	गलत
गुड़गांव	5.03	3.50	फरीदाबाद	5.75	1.50
अम्बाला	2.10	1.80	यमुनानगर	1.80	1.44
रोहतक	1.90	1.71	पानीपत	1.73	0.80

• प्रदेश भर में औसतन 36.2% प्रॉपर्टी आईडी में गड़बड़ियां हैं। अलग-अलग जिलों में 20 से 90% आईडी में गड़बड़ियां मिल रही हैं।



हिमाचल नगर निगम ऑफिस में प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने पहुंचे लोग।

### परेशानी: एनओसी, रजिस्ट्रियां नहीं हो पा रही

• बकाया प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज में 100% कूट का फायदा नहीं उठा पा रहे। • एनओसी नहीं मिल रही, नक्शा पास नहीं हो रहा। • प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, लोज, किराया नामा या हस्तांतरण के लिए अनापूर्त प्रमाणपत्र लेने में अड़चन आ रही है। • लोन पास नहीं हो रहे।

- 15% गलत है तो दोबारा सर्वे करना होगा और प्रति यूनिट तय रेट का 4 गुना जुर्माना वसूला जाएगा।
- सर्वे 20% या इससे ज्यादा गलत है तो टेंडर रद्द कर दिया जाएगा।

### सीधी बात

कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री

इतने बड़े सर्वे में थोड़ी खामियां तो आएंगी ही

Q. शहरों में जो प्रॉपर्टी सर्वे कराया है, उसमें इतनी गड़बड़ी कैसे हो गई?

A. इतने बड़े सर्वे में थोड़ी बहुत खामियां आते हैं। जनता को सहयोग करना चाहिए। ऐसा उदा। पूरे देश में किसी प्रदेश का नहीं है।

Q. सर्वे को पार्लट व मेयर तक ने मलत करार दे दिया है। क्या कर्हमे?

A. हमने 1-1 इन जमीन नाप दी। छोटी-छोटी गलतियां हुई हैं। किसी के नाम को गलती है, किसी का साइज गलत है। कुछ भ्रष्टियां तो आएंगी ही। अब उन 35 लाख प्रॉपर्टी मालिकों को डर खार जा रहा है, जो टैक्स नहीं दे रहे थे। अब उन्हें टैक्स देना होगा और वेनामी प्रॉपर्टी खून गई।

Q. गलती वाली कंपनी ने की है। जनता परेशान है। गड़बड़ियां ठीक कैसे करेंगे?

A. हम इसे सुधारने के लिए तैयार हैं। हमने जनता को न्योता दिया है कि आए और ऑब्जेक्शन दें।

Q. स्कीम की कॉन्डिशन में भी विकास एतुक लगाया है। क्या कर्हमे?

A. जिन स्कीम की कॉन्डिशनियां या एचएमवीपी के संकर में डेवलपमेंट चार्ज लिया जा चुका है, उन्हें यह चार्ज नहीं देना।

Handwritten signature

the erroneous data entries. No additional payment would be made for re-survey.

- 3. For submitted property survey data of any land/ asset property, if there is more than 10 % and upto 15% of error identified by the Audit Agencies 4 \* 'X'  
Where X= Price Quoted by the Bidder for property survey. The bidder shall be penalized 4 times the rate quoted for the number of properties in which errors were identified by the audit agencies. The Successful Bidder(s) shall be required to perform re-survey of the identified properties and correct the erroneous data entries. No additional payment would be made for re-survey.
- 4. For submitted property survey data of any land/ asset property, if there is more than 15 % and upto 20% of error identified by the Audit Agencies 8 \* 'X'  
Where X= Price Quoted by the Bidder for property survey. The bidder shall be penalized 8 times the rate quoted for the number of properties in which errors were identified by the audit agencies. The Successful Bidder(s) shall be required to perform re-survey of the identified properties and correct the erroneous data entries. No additional payment would be made for re-survey.
- 5. For submitted property survey data of any land/ asset property, if there is more than 20 % of error identified by the Audit Agencies Termination of Contract without clearing any of the pending invoices
- 6. For completion of survey in the defined timelines as per the time schedule given in Request for Proposal (RFP) in case the survey is not completed in the defined timelines as specified in the Request for Proposal (RFP) the bidder shall be charged 1% per month penalty on the balance amount to be paid for survey maximum upto 10%, beyond which the contract shall be terminated without clearing any of the pending invoices



V.I.P

**41.5.1. Error Definitions:**

In the above table error shall mean any one of the following:

- a) Errors in capturing internal measurements such as carpet area and Plot area etc. This shall be validated against the data captured by validation/audit agencies. Differences in the measurements upto 10% can be ignored. But for more than 10% it shall be considered as an error.
- b) Data Captured for all mandatory fields shall be validated by the audit agencies for all the fields other than those mentioned in (a).
- c) Discrepancies between the data captured by survey agencies and audit agencies shall be analysed and accordingly errors shall be calculated.



Maximum Penalty applicable to the bidder shall not exceed 10% of the Total Work Order value till the completion of property survey. If the total Penalty exceeds beyond 10%, it would be considered as non-conformance to the Quality of Services and may lead to termination of the Contract and Directorate of Urban Local Bodies (DULB) may on their sole discretion cancel the order and go afresh with the entire property survey exercise without clearing any of the pending payment of the bidder and forfeiting the performance bank guarantee submitted by the bidder after receiving the order.

**41.6. Issue Management Procedures**

**41.6.1. General**

- a) Issue Management process provides for an appropriate management structure towards



Handwritten signature

- Obtain suggestions for change to improve the services levels
  - Penalties shall be imposed either quarterly or on immediate next payment milestone etc.
- k) In case desired, Directorate of Urban Local Bodies (DULB) may initiate an interim review to check the performance and the obligation of the System Integrator. The Service Level Agreement (SLA) may be reviewed and revised in accordance to the procedures detailed in Schedule 2, Change Control Schedule.
  - l) For the purpose of recovery of penalty imposed, the penalty amount shall be adjusted against payment made to the System Integrator by Directorate of Urban Local Bodies (DULB) for the respective quarter. In case the penalty amount exceeds the payment being made to System Integrator by Directorate of Urban Local Bodies (DULB) for that quarter, it may be adjusted against performance bank guarantee.
  - m) Directorate of Urban Local Bodies (DULB) shall not make any payments for Production support requests/ tickets during the lifecycle of the project.
  - n) It is expressly agreed that in case some Service Level is not achieved by the System Integrator and such non-achievement is not solely attributable to the System Integrator then no penalty shall be imposed upon on System Integrator.
  - o) The System Integrator and the Directorate of Urban Local Bodies (DULB) may expressly or impliedly agree not to levy any penalty upon System Integrator for non-performance.

**41.5. Service Level Agreement (SLA) Monitoring**

- a) Service Level Agreement (SLA) monitoring shall be carried out by Directorate of Urban Local Bodies (DULB) based on Service Level Agreement (SLA) compliance report and Service Level Agreement (SLA) monitoring tool. Service Level Agreement (SLA) monitoring tool shall be put in place by the System Integrator which shall collate information as per defined Service Level Agreement (SLA) parameters. Reports of Service Level Agreement (SLA) compliance in the tool shall be updated as per agreed updated frequency and available for review by Directorate of Urban Local Bodies (DULB) designated authority.
- b) Every bill raised by the System Integrator needs to be accompanied with a compliance report against applicable Service Level Agreement (SLA) depending on the phase and should also include self-declaration of compliance / non-compliance by the System Integrator. Bills need to include any other documents required by Directorate of Urban Local Bodies (DULB)
- c) Service Level Agreement (SLA)s related to validation of 10% of surveyed land/building assets

Serial. Number.	Service Level	Penalty
1.	For submitted property survey data of any property, if there is up to 5% of error identified by the Audit Agencies	No penalty imposed. The Successful Bidder(s) is required to perform re-survey of the identified properties and correct the erroneous data entries. No additional payment would be made for re-survey.
2.	For submitted property survey data of any land/ asset property, if there is up to 10 % of error identified by the Audit Agencies	2* 'X' Where X= Price Quoted by the Bidder for property survey. The bidder shall be penalized 2 times the rate quoted for the number of properties in which errors were identified by the audit agencies. The Successful Bidder(s) shall be required to perform re-survey of the identified properties and correct



*Handwritten signature*

the erroneous data entries. No additional payment would be made for re-survey.

- |   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | For submitted property survey data of any land/ asset property, if there is more than 10 % and upto 15% of error identified by the Audit Agencies | 4 * 'X'<br>Where X= Price Quoted by the Bidder for property survey. The bidder shall be penalized 4 times the rate quoted for the number of properties in which errors were identified by the audit agencies. The Successful Bidder(s) shall be required to perform re-survey of the identified properties and correct the erroneous data entries. No additional payment would be made for re-survey. |
| 4 | For submitted property survey data of any land/ asset property, if there is more than 15 % and upto 20% of error identified by the Audit Agencies | 8 * 'X'<br>Where X= Price Quoted by the Bidder for property survey. The bidder shall be penalized 8 times the rate quoted for the number of properties in which errors were identified by the audit agencies. The Successful Bidder(s) shall be required to perform re-survey of the identified properties and correct the erroneous data entries. No additional payment would be made for re-survey. |
| 5 | For submitted property survey data of any land/ asset property, if there is more than 20 % of error identified by the Audit Agencies              | Termination of Contract without clearing any of the pending invoices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6 | For completion of survey in the defined timelines as per the time schedule given in Request for Proposal (RFP)                                    | In case the survey is not completed in the defined timelines as specified in the Request for Proposal (RFP) the bidder shall be charged 1% per month penalty on the balance amount to be paid for survey maximum upto 10%, beyond which the contract shall be terminated without clearing any of the pending invoices                                                                                 |



V.I.P

**41.5.1. Error Definitions:**

In the above table error shall mean any one of the following:

- a) Errors in capturing internal measurements such as carpet area and Plot area etc. This shall be validated against the data captured by validation/audit agencies. Differences in the measurements upto 10% can be ignored. But for more than 10% it shall be considered as an error.
- b) Data Captured for all mandatory fields shall be validated by the audit agencies for all the fields other than those mentioned in (a).
- c) Discrepancies between the data captured by survey agencies and audit agencies shall be analysed and accordingly errors shall be calculated.



Maximum Penalty applicable to the bidder shall not exceed 10% of the Total Work Order value till the completion of property survey. If the total Penalty exceeds beyond 10%, it would be considered as non-conformance to the Quality of Services and may lead to termination of the Contract and Directorate of Urban Local Bodies (DULB) may on their sole discretion cancel the order and go afresh with the entire property survey exercise without clearing any of the pending payment of the bidder and forfeiting the performance bank guarantee submitted by the bidder after receiving the order.

**41.6. Issue Management Procedures**

**41.6.1. General**

- a) Issue Management process provides for an appropriate management structure towards

*[Handwritten signature]*



*[Faint official text]*

- g) The Service Level Agreement (SLA) shall be entered into concurrently with this Agreement between Directorate of Urban Local Bodies (DULB) and System Integrator.

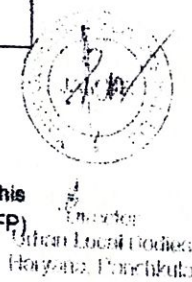
41.2. Definitions

- a) For purposes of this Service Level Agreement (SLA), the definitions and terms as specified in the contract along with the following terms shall have the meanings set forth below:
- "Availability" shall mean the time for which the services and facilities offered by the System Integrator are available for conducting operations from the implemented solution.
  - "Downtime" is the time the services and facilities are not available to Directorate of Urban Local Bodies (DULB) and Urban Local Bodies (ULB) and excludes the scheduled outages planned in advance for the implemented solution.
  - "Helpdesk Support" shall mean the System Integrator's 24x7x365 centre which shall handle Fault reporting, Trouble Ticketing and related enquiries during this contract.
  - "Incident" refers to any event / abnormalities in the functioning of the solution / Services that may lead to disruption in normal operations.
  - **Severity for Problem Requests/Defect Fixes:** The severity of a problem request or defects fixes would be based on the business impact of the problem.
- b) Severity is defined as follows:

Severity	Definition
Critical	<u>For Live Operations:</u> Showstoppers involving major functional failure in the system / solution. There are no usable workarounds available to troubleshoot the problem. <u>For UAT:</u> Fatal Errors like General Protection Fault, system hangs and testing cannot proceed till error is fixed.
High	<u>For Live Operations:</u> Users face severe functional restrictions in the system / solution irrespective of the cause. Workarounds are time consuming. <u>For UAT:</u> Serious Program behavior inconsistent to functional requirements, or data rendered inconsistent and testing cannot proceed in that area till error is fixed.
Medium	<u>For Live Operations:</u> Moderate functional restrictions in the system / solution irrespective of the cause. Has a convenient and readily available workaround. Affects a few users. <u>For UAT:</u> Minor errors to be corrected, but testing can proceed with work around solutions.
Low	<u>For Live Operations:</u> Requiring cosmetic functional changes. Does not require any workaround. It may include user query / suggestions but has no business impact. <u>For UAT:</u> Suggestions/ Comments. Improves user-interface or functionality. General remarks not necessarily meant for improvement.

41.3. Description of Services Provided

The required scope and boundaries of solution and services provided as part of this Agreement are detailed in Volume-II – Scope of Work of this Request for Proposal (RFP) document



41.4. Breach Clause

V.I.P.  
W. J. Singh

- a) This Service Level Agreement (SLA) document provides for minimum level of system characteristics and services required as per contractual obligations based on performance indicators and measurements thereof. The System Integrator shall ensure provisioning of all required services while monitoring the performance of the same to effectively comply with performance levels.
- b) Service Level Agreement (SLA) parameters shall be monitored on a monthly/quarterly basis (or as specified below) as per the individual Service Level Agreement (SLA) parameter requirements. In case the service levels cannot be achieved at service levels defined in the tables below, it shall result in a breach of contract and shall invoke penalty.
- c) A Service Level breach shall occur if the System Integrator fails to meet Minimum Service Levels on a monthly basis (or periodicity defined) for a particular Service Level.
- d) However, penalty would be levied every quarter or as specified below. The percentage of Service Level Agreement (SLA) violation would be the average of monthly Service Level Agreement (SLA) measurements for the months in that respective quarter.
- e) Overall Availability and Performance Measurements shall be on a quarterly basis for the purpose of Service Level reporting. Month wise "Availability and Performance Report" shall be provided by the System Integrator every quarter and a review shall be conducted based on this report. Availability and performance report provided to the Directorate of Urban Local Bodies (DULB) shall contain the summary of all incidents reported and associated performance measurement for that period.
- f) Before Centralized System Operations and Maintenance Phase and during the Centralized System Implementation/ Development Phase, the maximum penalty shall be capped at 10% of the total Project Value. If the penalty during these phases exceeds 10% of the Total project value, then Directorate of Urban Local Bodies (DULB) reserves the right to terminate the contract.
- g) During Centralized System Operations and Maintenance Phase, penalty per quarter are capped at 10% of that quarter's payment.
- h) If penalty calculations exceed 10% of the quarterly payment for two consecutive quarters, then Directorate of Urban Local Bodies (DULB) can take appropriate action including termination of the contract and forfeiting of Performance Bank Guarantee.
- i) In case there are successive breaches of Service Level Agreement (SLA's) for two quarters, Directorate of Urban Local Bodies (DULB) can issue show cause notice to the System Integrator to explain their non-performance. Also Steering Committee meeting may be called wherein System Integrator needs to explain the action taken to prevent such recurrences in future. This is without prejudice to other rights of Directorate of Urban Local Bodies (DULB).
- j) The services provided by the System Integrator shall be reviewed by Directorate of Urban Local Bodies (DULB) in terms of, but not limited to, the following:
- Check Performance of the System Integrator against this Service Level Agreement (SLA) every quarter and consider any key issues of the past period's performance statistics including major incidents
  - Discuss escalated problems, new issues and matters still outstanding for resolution
  - Increase Service Level Agreement (SLA) penalties if System Integrator is found to be defaulting on certain parameters repeatedly
  - Review of statistics related to rectification of outstanding faults and agreed changes

*[Handwritten Signature]*

*[Official Stamp]*  
 Director  
 Directorate of Urban Local Bodies

# पानीपत भास्व

पंच  
पंडित प्रो. वि.

वार रात्रि 08:  
री 1444, मुस्  
30 अप्रैल।  
03:30 तक र

2023

समाचारिका • वार्ता • इतराणा

समाजिकी • मतलौडी • रिवाजसरी

पानीपत भास्व 24 व. 30 अप्रैल 2023

## मंडे बिग स्टोरी • प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी गलतियां ठीक करना बड़ी चुनौती प्रॉपर्टी आईडी पोर्टल को एक साल पूरा हुआ; 62 हजार शिकायतों में से 20 हजार ही सुधरी

रिपोर्ट करने के लिए सिर्फ 2 कर्मचारी, 14 अफसरों के साइन के बाद ठीक होती हैं शिकायतें  
सुभाष राव | पानीपत

प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी गलतियां ठीक करना हरवासियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी। लोगों की सहूलियत के लिए ठीक एक साल पहले सरकार ने जो एनडीसी पोर्टल शुरू किया, वो अब तक कारगर साबित नहीं हुआ। नगर निगम की रिपोर्ट कहती है कि इस दौरान 2,205 लोगों ने प्रॉपर्टी संबंधी शिकायतें की। जसमें से 20,765 यानी 33 प्रतिशत की गलतियां ठीक हुईं। 38,110 आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। 3,090 आवेदन पेंडिंग हैं।

प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने के लिए हस्ताक्षरों का झमेला सबसे बड़ी बाधा है। नाम और पता प्रकृत करने के लिए भी 14 अफसरों के साइन होते हैं। इन 14 में से सिर्फ 2 कर्मचारी ही मौके पर जाकर रिपोर्ट बनाते हैं। यासी कंपनी के सर्वे के मुताबिक 1,72,301 प्रॉपर्टी आईडी हैं। जबकि निगम के रिकॉर्ड में 1,45,795 प्रॉपर्टी आईडी थीं। 26,506 प्रॉपर्टी आईडी नई बनीं। डेटा मिलान में पानीपत निगम बहुत पीछे है। डेट लेवल पर 7.38 प्रतिशत प्रॉपर्टी आईडी का मिलान रह गया है। जबकि पानीपत में अभी 28,435 यानी 19.50 प्रतिशत का डेटा मिलान नहीं हुआ। समालखा नगर पालिका में स दौरान 48.55 प्रतिशत शिकायतें हल की गईं। पालिका की तरफ से 739 फाइलें पेंडिंग हैं। वहीं पब्लिक के आधार पर सिर्फ 2 के नाम पेंडिंग हैं।

### 2 उदाहरणों से समझें सिस्टम कितना दुखदायी



#### भाजपा के सीनियर पार्षद को 3 महीने चक्कर काटने पड़े

भाजपा के पार्षद संजीव दहिया ने भगत कॉलोनी में 50 वर्ग गज प्रॉपर्टी की एनडीसी के लिए 25 नवंबर 2022 को आवेदन किया। जो 31 जनवरी को रिजेक्ट हो गया। 1 फरवरी को दोबारा आवेदन किया। निगम कर्मचारी बहाने बनाता रहा। फिर सर्वेयर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने लटकवाया। 19वें दिन रिजेक्ट कर दिया। 3 मार्च को तीसरी बार आवेदन हुआ और नए कमिश्नर और डीएमसी के हस्तक्षेप से 25 अप्रैल को एनडीसी जारी हुई।

#### पूर्व विधायक की नई और पुरानी प्रॉपर्टी आईडी मिलान नहीं

जाटल रोड पर ही समालखा के पूर्व विधायक रविंद्र मच्छरीली की एक दुकान है। इसकी नई और पुरानी प्रॉपर्टी आईडी का मिलान होना है। सूत्र बताते हैं कि 5 महीने से यह काम नहीं हो रहा है। चूंकि, यह एरिया अन-अप्लूड में डाल दिया है इसलिए अब तो नगर निगम कमिश्नर के पास भी पावर नहीं है। इसे यानी लेवल-3 को ठीक करने की।

### प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने का ऑनलाइन प्रोसेस जानिए

पहली कार्रवाई - ऑनलाइन आवेदन  
वार्ड क्लर्क फाइल तहसीलदार को देगा। तहसीलदार के साइन के बाद कानूनगो, फिर पटवारी के पास फाइल जाएगी।  
• कागजी कार्रवाई : सर्वेयर यानी सुपरवाइजर मौके पर जाकर देखता है कि प्रॉपर्टी है भी या नहीं।  
पटवारी के पास शुरू  
• वार्ड क्लर्क के पास फाइल।  
• टैक्स सुपरिंटेंड, डीएमसी डीटीपी व एटीपी के पास फाइल घुमेगी।  
दूसरी कार्रवाई - बिल्डिंग इंस्पेक्टर मौका देखकर सर्वेयर रिपोर्ट चेक करेगा।

इसी रास्ते फाइल वापस होती है: एटीपी, डीटीपी, डीएमसी, टैक्स सुपरिंटेंड और फिर वार्ड क्लर्क के पास।

• यहां पर वार्ड क्लर्क लेवल-1 (प्रॉपर्टी आईडी में नाम, मोबाइल नंबर, पता आदि) की ठीक करता है।

• यहां पर डीटीपी लेवल-2 (प्रॉपर्टी का एरिया आदि) की गलती ठीक करता है। अवैध कर दिया तो चंडीगढ़ की दौड़: पहले अगर एरिया अवैध में दिखता था तो निगम कमिश्नर ठीक करते थे, अब चंडीगढ़ फाइल जाएगी। वहीं से ठीक होगी।

### सीधी बात

विनोद नेहरा, डिप्टी निगम कमिश्नर

#### दावा... जल्द खत्म होगा झंझट

Q. एक काम के लिए 14 साइन की जरूरत क्यों पड़ती है?

A. इसी को खत्म करने के लिए प्रॉपर्टी आईडी के डेटा को पूरी तरह ऑनलाइन किया जा रहा है। नए आईडी व पुराने एनडीसी के 1.17 लाख से अधिक डेटा का मिलान हो चुका है। एक बार ऑनलाइन हो जाए तो कागजी कार्रवाई खत्म हो जाएगी।

Q. इतनी बड़ी संख्या में आवेदन रिजेक्ट क्यों किए जा रहे?

A. पोर्टल पर जब भी आप आवेदन करें तो ख्याल रखें कि संबंधित कागज लगाएं। बिना कागज के लगाएंगे तो फाइलनी वह रिजेक्ट होना ही है।

Q. निकाय मंत्री ने हार्दोन से 50 कर्मों दिलाकर 30 अप्रैल तक प्रॉपर्टी आईडी का झंझट खत्म करने को कहा था?

A. हार्दोन को लेटर लिख चुके हैं। जल्दी ही वहां से कर्मचारी मिलने जा रहा है, जिससे इंटीग्रेशन यानी प्रॉपर्टी आईडी के मिलान का काम ही पूरा कराएंगे।

#### डिटेल् इन ब्रीफ

प्रॉपर्टी आईडी	1,72,301
कुल एनडीसी डेटा	1,45,795
इंटीग्रेटेड (मिलान)	1,17,360
नॉन-इंटीग्रेटेड	28,435
प्रॉपर्टी टैक्स के आवेदन पेंडिंग	3390

*(Handwritten signature)*



#### 40. Schedule IV: Governance Schedule

##### 40.1. Purpose

The purpose of this Schedule is to:

- a) Establish and maintain the formal and informal processes for managing the relationship between the Directorate of Urban Local Bodies (DULB) and the System Integrator (including the outputs from other Schedules to this Agreement;
- b) define the principles that both Parties wish to follow to ensure the delivery of the Services
- c) Ensure the continued alignment of the interests of the Parties;
- d) Ensure that the relationship is maintained at the correct level within each Party;
- e) Create the flexibility to revise and maintain the relationship and this Agreement during the Term;

Set out the procedure for escalating disagreements; amenable contract administration and performance management.

##### 40.2. Governance Structure

###### 40.2.1. Project Monitoring Committee (PMC)

- (i.) The Parties shall, in addition to the purposes mentioned in the Clause 3.3, form a committee to be called as the project Monitoring committee for the purpose of day to day decision making and representation to complete the Project within fifteen (15) days of contract signing
- (ii.) The above referred project Monitoring committee shall hold project review meetings chaired by Director of Directorate of Urban Local Bodies (DULB). The Monitoring committee shall comprise of following members, and would meet formally on a fortnightly / monthly / quarterly, as required, basis at a time and location to be agreed between them.
- (iii.) Roles and Responsibilities of Project Monitoring Committee shall be as follows:
  - 1) Review and Validate System Integrator milestone / deliverables signoff report and provide recommendation in consultation with Directorate of Urban Local Bodies (DULB) / with a copy to steering committee
  - 2) Resolve and provide directions on the operational matters
  - 3) Monitor the project work schedule / plan as per the format provided in the Annexure VII to be submitted by System Integrator on a regular basis to ensure its implementation as agreed between System Integrator and Directorate of Urban Local Bodies (DULB). Ensure progress on training and capacity building activities to Urban Local Bodies (ULB), and concerned stakeholders as per the agreed scheduled
  - 4) Conducting regular meetings with key project stake holders for issue resolution
  - 5) Coordination between different stake holders as per the guidance of steering committee
  - 6) Any other issues to be discussed pertaining to the project
  - 7) To issue acceptance / Sign - off certificate to System Integrator as per their request during the Project period. The approval given by Project Monitoring Committee (PMC) shall be treated as sign-off issued by the Client for the respective milestone to System Integrator during the Project period
  - 8) To approve the release of payment to System Integrator during the Project period

The Project Monitoring Committee (PMC) shall comprise of the following members

*[Handwritten signature]*



Composition	
Director, Directorate of Urban Local Bodies (DULB)	Chairman
Project Director – Directorate of Urban Local Bodies (DULB)	Member Secretary
Chief officer of one municipal council from each category (A, B, and C)	Member
Commissioner / Dy. Commissioner of one Municipal corporation	Member
Representatives of Urban Development Department.	Member
Project Manager – System Integrator	Member
Project Manager, Project Management Unit (PMU)	Member
Other invitees, as per approval of Chairman	Member

- The relationship under this Agreement shall be managed by the Project Managers appointed by each Party, who shall provide the interface between the executive management of the respective Parties.
- Within seven (7) days following the Effective Date, Directorate of Urban Local Bodies (DULB) or its nominated agencies and the System Integrator shall each appoint a Project Manager. In the event that either Party wishes to substitute its Project Manager it shall do so in manner in which the original appointment is made and notify the other Party of such substitution as soon as reasonably practicable but at the latest within seven (7) days of the substitution.
- The Project Managers shall have responsibility for maintaining the interface and communication between the Parties.
- In the event that there is any material factor which affects the delivery of Services or the terms of payment as stated in the Terms of Payment Schedule, the Parties agree to discuss with the Project Monitoring Committee (PMC), any appropriate amendment to this Agreement or any Service Level Agreement (SLA)s or Statement of Works (including any variation to the terms of payment as stated in the Terms of Payment Schedule). Any variation so agreed shall be implemented through the change control procedure as set out in the Change Control Schedule, and should be put up to steering committee for approval

#### 40.2.2. Steering Committee

A Steering Committee under the chairmanship of Hon'ble Chairman, Directorate of Urban Local Bodies (DULB) shall be formed and shall govern the project till the Completion and would consist of following members:

Serial Number.	Designation	Position
1.	Director General	Chairman
2.	Joint Director	Member secretary
3.	Superintending Engineer- IT	Member
4.	Finance Representative	Member
5.	Superintendent, Establishment	Member
6.	Any other representative as desired by the Chair	Member
7.	Project Consultant	Member

*M. M. Khan*



Urban Local Bodies  
Maharashtra, Maharashtra

The Steering committee members shall meet at least once a month or as required based on the time and location agreed between them. These meetings shall cover as a minimum agenda:

- 1) Hold the kick-off meeting on the project with all stakeholders within seven (7) days of contract sign-off
- 2) Provide overall leadership, vision, and direction for the implementation of the project
- 3) Overall planning, co-ordination, monitoring and progress review of the project
- 4) Overall strategic control and take decision on regulatory matters and provide guidance for successful execution of the project
- 5) Approval of the detailed project work plan (including Gant chart representation) initially, as well as approvals to any subsequent changes necessary to be made in the plan. Post Steering Committee's approvals, the plan's adherence monitoring shall be the responsibility of the Project Monitoring Committee (PMC).
- 6) Creating a supporting environment for the success of the project
- 7) Consideration of matters arising out of the change control note and approval of the same
- 8) Resolution of disputes if any between System Integrator and Project Monitoring Committee (PMC)
- 9) Review of budgetary requirements and financial monitoring of the allocated funds

#### 40.3. Governance Procedures

- a) The System Integrator shall document the agreed structures in a procedures manual.
- b) The agenda for each meeting of the Project Monitoring Committee (PMC) shall be set to reflect the discussion items referred to above and extraordinary items may be added either with the agreement of the Parties or at the request of either Party. Copies of the agenda for meetings of the Project Monitoring Committee (PMC), along with relevant pre-reading material, shall be distributed at least one week in advance of the relevant meeting.
- c) All meetings and proceedings shall be documented such documents to be distributed to the Parties and copies shall be kept as a record. All actions, responsibilities and accountabilities arising out of any meeting shall be tracked and managed.
- d) The Parties shall ensure as far as reasonably practicable that the Project Monitoring Committee (PMC) shall resolve the issues and resolve the objectives placed before them and that members representing that Party are empowered to make relevant decisions or have easy access to empowered individuals for decisions to be made to achieve this.
- e) In order formally to submit a Disputed Matter to the aforesaid for a, one Party ("Claimant") shall give a written notice ("Dispute Notice") to the other Party. The Dispute Notice shall be accompanied by
  - f) A statement by the Claimant describing the Disputed Matter in reasonable detail and
  - g) Documentation, if any, supporting the Claimant's position on the Disputed Matter.
- h) The other Party ("Respondent") shall have the right to respond to the Dispute Notice within seven (7) days after receipt of the Dispute Notice. In the event that the parties are unable to resolve the Disputed Matter within a further period of seven (7) days, it shall refer the Disputed Matter to next level of the dispute resolution for action.
- i) All negotiations, statements and / or documentation shall be without prejudice and confidential (unless mutually agreed otherwise).
- j) If the Disputed Matter is having a material effect on the operation of the Services (or any of them or part of them) the Parties shall use all their respective reasonable endeavours to reduce the elapsed time in reaching a resolution of the Disputed Matter.

Director  
 Information Services  
 Government of Karnataka

*(Handwritten Signature)*